लोकतंत्र और छात्र राजनीति

सुदीप (शोधार्थी)
राजनीति विज्ञान विभाग,
मेरठ कॉलेज, मेरठ।

सारांश :

जब भी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का समय आता है तो प्रश्न उठता है कि क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने में छात्र न केवल सामाजिक निगरानी का कार्य करते हैं बल्कि सत्ता तक को हिलाने की भी शक्ति रखते हैं। यदि इतिहास पर दृष्टि डालें तो छात्र आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है जिसमें चीन में सन् 1989 में थ्यानमैन चौक पर लोकतंत्र की मांग कर रहे छात्रों को कुचला जाना वर्तमान समय की छात्र राजनीति और छात्र आंदोलनों के लिए एक उदाहरण है। भारत में यदि छात्र आंदोलनों की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व और स्वात्रंत्योत्तर भारत में जितने भी परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलन हुए है उनमें छात्रों की अहम भूमिका रही है, परंतु उनकी स्वतंत्र पहचान नहीं थी। जबकि स्वतंत्रता के उपरांत जितने भी आंदोलन हुए उनके मूल में सामाजिक –राजनीतिक परिवर्तन की चाह थी। परंतु वर्तमान समय की छात्र राजनीति में मुखर रहने वाले छात्र नेता राजनीति के धरातल पर सही साबित नहीं हो रहे हैं और भविष्य की राजनीति के लिए कोई नई आस नहीं जगा पा रहे हैं। संभवतः इसका एक बड़ा कारण वर्तमान में देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों के छात्र संघ और छात्र नेताओं का विभिन्न राजनीतिक दलों की कठपुतली बन जाना है। अतः वर्तमान में छात्र संघ और छात्र राजनीति को रचनात्मक स्वरूप देने की आवश्यकता है, हरपना कि विभिन्न राजनीतिक दलों की कठपुतली बनने की।

मुख्य शब्दः छात्र राजनीति,राजनीतिक परिवर्तन, युवा–पीढ़ी, सकारात्मक राजनीति।

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

प्रस्तावना :–

जब भी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में चुनाव का समय आता है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? किसी भी देश की राजनीति में युवाओं की अहम भूमिका होती है। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ी युवा आबादी एवं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में युवा –छात्रों के द्वारा ही देश का निर्माण होता है। इसलिए भारत की राजनीति में भी युवा– छात्रों का नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र संघ चुनाव होते हैं।क्योंकि यहीं से छात्र राजनीति का शुभारंभ होता है। छात्र राजनीति के संदर्भ में शहीद भगत सिंह ने 1928 में अपने लेख में कहा था कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। जैसा कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि –

"जब सड़के खामोश हो जाती है,

तो संसद आवारा हो जाती है।"

छात्र ने केवल सामाजिक निगरानी का कार्य करते हैं बल्कि सत्ता तक को हिलाने की शक्ति भी रखते हैं।

परंतु लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि कभी–कभी छात्र संघ चुनाव में छात्र राजनीति को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। मुख्यतः इसका कारण यह है कि छात्र राजनीति में असामाजिक तत्वों, जातिवादी, संप्रदाय, क्षेत्रवाद के बढ़ते दबाव के कारण उच्च शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक माहौल बिगड़ने के साथ–साथ कानून व्यवस्था के लिए भी यह गंभीर समस्या बन जाती है। परिणामस्वरूप छात्र संघ चुनाव शैक्षणिक व्यवस्था पर भी प्रभाव डालते हैं।

लोकतंत्र

भारत में छात्र राजनीति की दशा व दिशा को समझने से पूर्व लोकतंत्र के राजनीतिक पहलू को जानना आवश्यक है।

लोकतंत्र क्या है? सामान्यतः यह शासन प्रणाली के रूप में एक आधुनिक विचारधारा है जिसमें जनता द्वारा ही निर्णय किया जाता है कि शासन कैसे चलाया जाए। जो कि लोकतंत्र का राजनीतिक पक्ष है। अपितु जब हम लोकतंत्र को जीवन पद्धति व मूल्यों के संदर्भ में देखते हैं तो व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक व आर्थिक उद्देश्य इसमें निहित हो जाते हैं। इस प्रकार जब हमारे सोचने का तरीका उदारवादी होता है तो हम मनुष्य की गरिमा व उसके विवेक का सम्मान करते है तो हम कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक व्यक्तित्व है। जब यही विचार पद्धति सम्पूर्ण समाज व संस्कृति के विविध पक्षों में स्थापित हो जाती है तो लोकतांत्रिक समाज व संस्कृति का निर्माण होता है। जहां तक भारतवर्ष की बात की जाये तो भारत में संस्कृति के रूप में लोकतंत्र हमेशा विद्यमान रहा है। भारतीय उपनिषदों में उल्लिखित 'मुण्डे – मुण्डे मतिभिन्ना "व' सर्वे भवन्तु सुखिनः" स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया जाता रहा है। फिर इसका स्वयं में सबसे बड़ा प्रमाण है भारत की सामाजिक संस्कृति जो तरह – तरह की विविधताओं को धारण करती आई है तथा अन्तर्विरोधों को ग्रहण करते हुए एक नये रूप में उभरती आयी है। इस संदर्भ में भारतीय संस्कृति अद्वितीय है कि किसी भी

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

सामाजिक संस्कृति का विकास लोकतांत्रिक मूल्य पद्धति के अभाव में नहीं हो सकता है, तथा न केवल सांस्कृतिक विरासत के रूप में बल्कि स्वंतत्रता संघर्ष के दौरान भी भारतीयों ने लोकतंत्र के विविध आयामों के प्रति अपनी स्वतंत्र व मौलिक दृष्टि विकसित की। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष न केवल सत्ता प्राप्ति का बल्कि यह एक विचारात्मक संघर्ष भी था जिसमें स्पष्ट सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दर्शन थे और ये सभी दर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों से ही अनुप्राणित थे। वैचारिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, महिला उत्थान, दलित उत्थान, सामाजिक – आर्थिक न्याय, बंधुता जैसे मूल्य हमारे द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अर्जित किये गये और इस प्रकार भारतीय नेताओं के समक्ष भविष्य में लोकतांत्रिक भारत का स्पष्ट स्वरूप उभरता है।

छात्र राजनीति :–

राजनीति, शासन एवं नीति अर्थात् उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला है। दूसरे शब्दों में, नीति विशेष के द्वारा शासन करना अथवा विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। साधारण शब्दों में कहे तो राजनीति, जनता के सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाना राजनीति कहलाता है। राजनीति में बहुत से मार्ग अपनाये जाते हैं जैसे– राजनीतिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना। राजनीति विभिन्न स्तरों पर हो सकती है जैसे – अन्तराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर आदि।

विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर छात्र नेतृत्व करने वाले छात्र जब कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध राजनीति करने लगे अथवा राजनीतिक दलों से संबंध रख कर स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भागीदारी देने लगे तो छात्र नेतृत्व छात्र राजनीति में परिवर्तित हो जाता है।

छात्र राजनीति की स्वतंत्रता से पूर्व से ही छात्र विभिन्न दृ विभिन्न राजनीति आंदोलनों में संलग्न रहा है। आंदोलन संगठित सत्ता तंत्र या व्यवस्था द्वारा शोषण और अन्याय के विरुद्ध उत्पन्न हुआ संगठित और सुनियोजित अथवा स्वतःस्फूर्त सामूहिक संघर्ष है। इसका उद्देश्य सत्ता अथवा व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन होता है। यह राजनीतिक सुधारों या परिवर्तन की आकांक्षा के साथ ही सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी चलाया जाता है। दृष्टिगत रूप में छात्र आन्दोलनों के अनेक कारण होते हैं जैसे शुल्क कम करना, छात्रवृत्ति बढ़ाना जैसे आर्थिक कारण, प्रवेश परीक्षा एवं अध्यापन के विभिन्न प्रतिमानों में परिवर्तन की माँग, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयो में प्रशासनिक कार्यों में विलम्ब होना, छात्रों व अध्यापकों के बीच टकराव, अपर्याप्त सुविधाएं जैसे – छात्रावासों की कमी, उनमें दिए जाने वाले खराब भोजन, पेयजल की सुविधाओं का अभाव तथा युवा नेताओं का राजनीतिज्ञ द्वारा भड़काया जाना। साथ ही साथ लोकतंत्र को जीवंत रखने और आम जनमानस के मुद्दों पर भी छात्रों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है।

वैश्विक परिदृश्य में छात्र राजनीति :–

इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो विश्व में छात्र राजनीति का लंबा इतिहास रहा है–

पड़ोसी देश चीन में छात्रों की अगुवाई में 1989 में थ्यानमेन चौक पर हजारों लाखों छात्र लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे तभी चीनी सेना ने छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोलियों और टैंकों से हमला किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और दर्जनों लोगों को फांसी दी गई तथा लगभग 10 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन को कुचलने के तरीके की चीन की विश्व भर में निंदा की गई।

संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्च, 1965 में मिशीगन विश्वविद्यालय में 200 अध्यापकों और छात्रों ने वियतनाम के विरुद्ध यूएसए की जंग के विरोध में सेमिनार का आयोजन किया और दैनिक चलने वाली कक्षाएं रद्द कर दी गई तथा 12 घंटे तक अपने ही देश के विरुद्ध रैलियां और सेमिनार हुए। मिशीगन विश्वविद्यालय ने इन सेमिनार व रैलियों को कैंपस में आयोजन करने की अनुमति दी।

सन् 1968 में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के हैमिल्टन हॉल पर डेरा डाल दिया था। इस घटना से पूर्व एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुलासा किया था कि वियतनाम युद्ध से जुड़ी एक लीडिंग कंपनी से विश्वविद्यालय के संबंध हैं। पुलिस ने जब छात्रों को विश्वविद्यालय से बाहर निकालने की कोशिश की तो वहां हिंसक टकराव हुआ। हालांकि अमेरिकी सरकार ने किसी छात्र पर राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया। बस कुछ प्रदर्शनकारी छात्र सस्पेंड किए गए।

सन् 1968 में फ्रांस में सरकार की नीतियों के विरुद्ध पेरिस के विश्वविद्यालयों से छात्रों द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में लगभग 11 लाख छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया। आंदोलन के परिणामस्वरूप फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डि गॉल को भागकर जर्मनी में शरण लेनी पड़ी थी तथा सरकार पूर्ण रूप से पंगु हो गई थी।

भारत में छात्र राजनीति की भूमिका :—

भारत में यदि छात्र राजनीति की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व और स्वात्रंत्योत्तर भारत में जितने भी परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलन हुए, उनमें छात्रों की अहम भूमिका रही है।भारत की स्वतंत्रता से पूर्व के सभी छात्र संघर्ष अविच्छिन्न रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे अथवा उन्हीं का एक लघुसंस्करण थे। उनकी स्वतंत्र पहचान नहीं थी, जबकि स्वतंत्रता के उपरांत जितने भी आंदोलन हुए उनके मूल में सामाजिक —राजनीतिक परिवर्तन की चाह थी।

भारत में सन् 1905 के स्वदेशी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। जो किसी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को दर्शाता है। इस आंदोलन का क्षेत्र और प्रभाव बहुत व्यापक था।उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सन् 1920—22 के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाये असहयोग आंदोलन में पूरे देश में शिक्षा का सामूहिक बहिष्कार हुआ, जिसमें लगभग 90,000 छात्रों ने स्कूल—कॉलेज छोड़ दिए और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया।उसी दौरान इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ सहित कई नए विश्वविद्यालयों की भी नींव रखी गई, जिन्होंने कालांतर में तमाम क्रांतिकारियों को पैदा किया, जो कि स्वतंत्रता के बाद छात्र आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुए। इनमें जेपी आंदोलन को प्रमुख माना जा सकता है, जिसने देश की

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

तात्कालिक तस्वीर को बदल दिया था।समाकालीन छात्र राजनीति में भी जेपी आंदोलन को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है।

इसके बाद सन् 1930–31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी कपड़ों और मदिरा के बहिष्कार में छात्रों ने विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असम में 'कनिंघम सर्कुलर' जिसमें छात्रों एवं उनके अभिभावकों से सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, इस सर्कुलर के विरोध में छात्रों द्वारा शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया था। सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हड़ताल की गई तथा छात्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़–चढ़कर भाग लिया।

स्वतंत्रता के उपरांत असम में छात्र आंदोलनों का बदलता स्वरूप देखा गया। 1950 के दशक में असमिया छात्रों के नेतृत्व में छात्र आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसमें राज्य सरकार की नौकरियों में असमी भाषी लोगों को प्राथमिकता देने तथा असमिया भाषा को राज्य की एकमात्र सरकारी भाषा एवं स्कूल तथा कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम बनाने की मांग रखी गयी। इसी कड़ी में असम में गैर–कानूनी आव्रजन का सवाल 1950 से ही उठता रहा, परन्तु 1979 के राज्य विधानसभा चुनावों में गैर–कानूनी प्रवासियों द्वारा मतदाता सूची में बड़ी संख्या में शामिल हो जाने पर इसके विरुद्ध ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (ए.ए.एस.यू.) ने 'असम गण संग्राम परिषद' के साथ मिलकर गैर–कानूनी प्रवासियों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया था। इस आंदोलन ने असमी बोलने वाले सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त किया।इस आंदोलन को इतना भारी जनसमर्थन प्राप्त हुआ था कि उस दौरान सोलह में से चौदह चुनाव क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो पाए थे।

दक्षिण के राज्यों में छात्र आन्दोलनों का अवलोकन करें तो इस संदर्भ में तमिलनाडु की चर्चा अपेक्षित है।वैसे तो हिन्दी तथा हिन्दी भाषियों के विरुद्ध मुहिम तमिलनाडु में लंबे अर्से से चल रही थी, परंतु इसके लिए छात्रों द्वारा किया संगठित आंदोलन 1965 मेंदेखने को मिला। 25 जनवरी, 1965 को छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन की व्यापकता के बारे में यह कहा जाता है कि तमिलनाडु में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रदर्शन में जितने लोगों ने भाग लिया उसकी संख्या सिर्फ इस एक दिन में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या से कम थी।इस दिन केवल चेन्नई में ही लगभग 50,000 छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसी तरह के अनेक प्रदर्शन तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में किए गए। जिसके बाद भड़की हिंसा में कई छात्र भी मारे भी गए।

सन् 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र – युवाओं की अगुवाई में तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की चूलें हिला दी थी। इस आंदोलन में छात्रों की न केवल राष्ट्रव्यापी भागीदारी रही बल्कि इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में एक नये अध्याय को जन्म दिया। इसी दौरान आपातकाल के समय जब देश में भय का माहौल था तब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को विश्वविद्यालय के छात्रों ने परिसर में नहीं घुसने दिया था। वस्तुतः इस आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई जहां जनवरी, 1974 में अनाज तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि से पैदा हुआ जनाक्रोश था, जो राज्य के शहरों और

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

महानगरों में छात्र आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। विपक्षी दलों ने शीघ्र ही इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। जिससे कुछ ही समय में राज्य में लगभग अराजकता छा गयी और हड़ताल, लूट—पाट, दंगे और आगजनी की घटनाएं घटती रहीं। जिसके जवाब में पुलिस ने भी अंधाधुंध गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज और गोलीबारी का सहारा लिया। किंतु फरवरी, 1974 में केंद्र सरकार को आंदोलन के सामने झुकना पड़ा तथा राज्य सरकार को त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पड़ा। गुजरात विधानसभा निलंबित कर दी गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

वर्तमान दौर में छात्र राजनीति का बदलता स्वरूप :—

यदि पिछले दो दशकों की यदि बात करें तो अन्ना आंदोलन और निर्भया गैंगरेप के विरोध में उठ खड़े हुए जनाक्रोश को छोड़ दे तो किसी जनहित से संबंधित मुद्दों पर छात्र आंदोलन नहीं हुआ और अधिकतर जो भी हुए हैं वह क्षेत्रीय मुद्दों अथवा विशेष वर्ग आदि के हित संवर्धन के लिए हुए। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के उपरांत सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाने के बाद देश भर में इसके विरोध में आंदोलन हुए, जो कि एक विशेष वर्ग के छात्रों का दूसरे वर्ग के छात्रों को मिलने वाले लाभ से चिढ़ थी अथवा ओबीसी वर्ग के हित वृद्धि को सहन न कर पाना था। पुनः सन् 2006 में यूपीए सरकार द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के उपरांत एक विशेष वर्ग के छात्रों के द्वारा ओबीसी के आरक्षण व्यवस्था का विरोध किया गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के विरोध में देशभर में हाल ही के दिनों में विपक्षी दलों द्वारा उकसाए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा अनेक शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से इसके विरोध में प्रदर्शन किए गए और उसकी आग देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में फैल गई जिसके फलस्वरूप हिंसक प्रदर्शन हुए और देश में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इंटरनेट सेवा भी कईं बार बंद करनी पड़ी। उन सब की पृष्ठभूमि में निवर्तमान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने चेतावनी भी दे डाली कि नरेंद्र मोदी सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली है। तो क्या ऐसे संस्थानों में जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की तैयारी चल रही है, सवाल उठना भी स्वाभाविक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जादवपुर और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय तक नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी पर विरोध के सुर निरंतर तेज हुए, जिसमें पर्दे के पीछे से किरदार विपक्षी दलों का है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के पास चेतावनी के साथ ही विपक्ष को कोसने का भी मुद्दा मिल गया। अब असल आवश्यकता इस बात की है कि छात्र राजनीतिक दलों के औजार न बने और उन्हें कोई दिग्भ्रमित न सके। इसके लिए प्रत्येक दल को आईने में झांकने की आवश्यकता है। आमतौर पर माना जाता है कि छात्र देश की राजनीति को नई दशा और दिशा देने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने अब तक छात्रों को अपने—2 तरीकों से उपयोग किया है।

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति का पाठ सीखने वाले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार,ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, अरुण जेटली आदि नेताओं ने मुद्दों की बात करते हुए अपनी सोच व कार्यप्रणाली से आम जनता के मन में एक नई आस का संचार किया। जिस रचनात्मक व सकारात्मक राजनीति की पहल इन्होंने की थी वही इन्हें समकालीन राजनीति में स्थापित किए हुए हैं। परंतु वर्तमान दौर के छात्र नेता राजनीति के धरातल पर सही साबित नहीं हो रहे हैं और भविष्य की राजनीति के लिए कोई नई आस नहीं जगा पा रहे हैं।

अपितु छात्र आंदोलनों में शामिल होने वाले छात्र राजनीति का ककहरा छात्र संघ चुनाव के द्वारा सीखते है।इसलिए सर्वप्रथम कॉलेज स्तर पर ही छात्रों में आदर्श राजनीति के आदर्श रूप को समाहित करने के प्रयास करने चाहिए –

लिंगदोह समिति की सिफारिशों को पूर्णतः लागू करने की आवश्यकता :–

वर्ष 2007 में छात्र संघ चुनावों में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता – जे . एम . लिंगदोह ने की थी। परंतु उनके द्वारा दिये गये सुझावों का छात्र संघ चुनावों में खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। लिंगदोह समिति की सिफारिशों को किस प्रकार से ठोस रूप दिया जाए यह प्रशासन के लिए वर्तमान में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में छात्र राजनीति की कई चुनौतियाँ है जिससे कई प्रकार की समस्याएँ खड़ी हो गयी हैं छात्र राजनीति किस प्रकार से अपने शुद्धतम् रूप में निखरे यह भी एक चुनौती है। लिंगदोह समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि इन सिफारिशों की समीक्षा इसे लागू करने के बाद अवश्य होनी चाहिए तथा इसमें प्रथम समीक्षा दो वर्ष पश्चात् और द्वितीय समीक्षा तीसरे या चौथे वर्ष में होनी चाहिए। समिति की इन सिफारिशों का आशय यह था कि छात्र संघ चुनाव के दौरान यदि किसी भी प्रकार की व्यावहारिक परेशानी आती हैं तो उनका समाधान किया जा सके। समीक्षा के दौरान समाज के विभिन्न वर्गो, प्राध्यापक, प्रशासन, छात्र समुदाय, छात्र संगठनों, बुद्धिजीवियों व छात्रों के अभिभावकों से उनकी राय व सुझाव लिये जायें और तद्नुसार छात्र प्रतिनिधित्व की मशीनरी छात्र संघ को दुरूस्त किया जाये।

छात्र राजनीति को उचित दिशा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाने आवश्यक हैः–

वर्तमान छात्र राजनीति की चुनौतियों के समाधान के लिए कॉलेज स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिए, जिससे कि वे हिंसात्मक आंदोलनों व कृत्यों से दूर रह सके –

- शैक्षणिक स्तर पर छात्र संघ चुनावों से सम्बन्धित नियमों व कानूनों को व्यावहारिक रूप में उतारना और उन्हें कठोर बनाने की आवश्यकता है जिससे कि छात्र राजनीति मैं आदर्शवाद समाहित हो सके।
- शैक्षणिक परिसर में छात्रों के एक संगठन को मान्यता दी जाए और बहुदलीय प्रणाली जैसी प्रथा न अपनायी जाए।क्योंकि एक से अधिक संगठन होने पर छात्रों में प्रतिस्पर्धा और द्वेष की भावना पनपती है.
- राजनीतिक दलों का छात्र संघ चुनावों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न हो तथा छात्र संघ चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखने वाले छात्र नेता का नामांकन रद्द कर दिया जाए।

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

- वर्तमान समय में चुनाव प्रचार के तौर – तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। प्रचार करने के लिए छात्रों की निर्धारित संख्या हो।
- वर्तमान समय में छात्रसंघ चुनाव के बिगड़ते स्वरूप पर नियंत्रण करना आवश्यक है जिसमें जिसमें धन – बल का अधिक प्रयोग हो रहा है।
- जे. एम. लिंगदोह समिति की सिफारिशों को कठोरतम् रूप से लागू किया जाए और सिफारिशों से सम्बंधित नियमों की विश्वसनीयता की नियमित जॉच समिति द्वारा की जाए।
- व्यक्तिगत हितों के लिए विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाने वाले छात्र नेताओं के ऊपर कार्यवाही हो।
- आपराधिक मुकदमों में फंसे छात्रों की भागीदारी प्रतिबंधित हो।
- सभी राजनीतिक दलों में छात्रों के राजनीति में भाग लेने के सम्बन्ध में एक आम आचार संहिता पर सहमति होनी चाहिए। यह उन्हें राष्ट्रीय भावनाओ और भविष्य में दायित्वों का निर्वाह करने के लिए तैयार करेगी। और यह विषय बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि पहले तो छात्रों को राजनीति से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाये और फिर उनसे आशा की जाये कि वे समाज निर्माण की प्रक्रिया में उत्साह से भाग लें जगह।

निष्कर्षः–

वर्तमान दौर की राजनीति के संदर्भ में यदि देखा जाए तो छात्र राजनीति में मुखर रहने वाले छात्र नेता राजनीति के धरातल पर सही साबित नहीं हो रहे हैं और भविष्य की राजनीति के लिए कोई नई आस नहीं जगा पा रहे हैं। संभवतः इसका एक बड़ा कारण वर्तमान में देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय के छात्र संघ और छात्र नेताओं का विभिन्न राजनीतिक दलों की कठपुतली बन जाना है। अतः वर्तमान में छात्र संघ और छात्र राजनीति को रचनात्मक स्वरूप देने की आवश्यकता है, ना कि विभिन्न राजनीतिक दलों की कठपुतली बनने की।यदि छात्र संघ सियासत के मोहरे बनना बंद कर दे तो छात्र युवा देश की राजनीति में मुख्य भूमिका अदा करने में विस्तृत रूप में सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि शिक्षित वर्ग ही लोकतंत्र को बचाने के लिए तत्पर नहीं होगा तो लोकतंत्र अरस्तु के कुलीन तंत्र (इने– गिने लोगों की सरकार) में परिवर्तित हो जाएगा और सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त होने की संभावना रहेगी। अतः छात्रों के कंधों पर ही लोकतंत्र को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। क्योंकि यही शिक्षित युवा पीढ़ी आगे चलकर देश का भविष्य तय करती है।

राम मनोहर जी ने सही कहा है कि–" जब छात्र राजनीति नहीं करते हैं तो वे सरकारी राजनीति को चलने देते है, जो कि समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक है।"

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. खंडेला, एम0 सी0 : भारतीय राजनीति का बदलता परिदृश्य, जयपुर, प्वाइंटर पब्लिशर्स।
2. युवा बदल सकते हैं तस्वीर, 'इंडिया टुडे', कनाट प्लेस, नई दिल्ली, के 0 8, अप्रैल, 2008, पृष्ठ 45।
3. कुमार, प्रदीप : आन्दोलन के नाम पर सिकती राजनीतिक रोटियाँ मुक्ता प्रेस, नई दिल्ली, फरवरी (द्वितीय) 1994, पृष्ठ 40।
4. छात्र संघों पर काली छाया 'आउटलुक', आउटलुक सफदरगंज, नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2006, पृष्ठ 3।

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

5. देश का भविष्य हैं छात्र, सियासत की चक्की में पिसने से बचाना होगा, 'दैनिक भास्कर', 10 जनवरी, 2020, पृष्ठ 06
6. http://thewirehindi.com/21494/allahabad-university-student-union-election/
7. https://www.dw.com/hi/india-delhi-students-protest-against-citizenship-amendment-act/a-51687675
8. https://m-hindi.webdunia.com/my-blog/about-jnu-120010600040_1.html?amp=1
9. https://navbharattimes.indiatimes.com/-/articleshow/822950.cms
10. https://m.patrika.com/lucknow-news/j-p-andolan-and-emergency-story-1245724/